श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा: सर, ये जो दो कोऑपरेटिव सैक्टर में हैं, ये दोनों ही मुनाफे में जा रहे हैं। इनमें कोई घाटा नहीं हो रहा है।

मध्य प्रदेश में वन कर्मियों के लिए वायरलैस सेट

*388. **श्री बालकवि बैरागी:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वृक्षों की अवैध कटाई की रोकथाम एवं अग्नि सुरक्षा हेतु केन्द्र सरकार मध्य प्रदेश के सभी वन कर्मियों को वायरलैस सेट प्रदान करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने वायरलैस सेट प्रदान किए गए हैं;

(ग) राज्य में वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान वनों में आग लगने के कितने प्रकरण हुए और उन्हें रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) वनों में वृक्षों की अवैध कटाई रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यावाही की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वन सुरक्षा, मुख्य रुप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और राज्य सरकारें, वन सुरक्षा कार्यकलापों के लिए "स्टेट प्लान" के अंतर्गत धनराशि की व्यवस्था करती है। तथापि, वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वायरलैस सेटों और अन्य उपकरणों की खरीद के लिए धनराशि प्रदान की जाती है।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत मध्य प्रदेश को 1215 वायरलैस सेटों की स्वीकृति दी गई है।

(ग) मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा आग लगने के निम्नलिखित प्रकरण सूचित किए गए हैं-

वर्ष	आग प्रकरणों की संख्या
1998-99	619
1999-2000	1012

अग्नि सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत सप्लाई किए गए उपकरणों के तत्काल उपयोग तथा स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया ।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को यह परामर्श दिया था कि वे वन सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाएं और संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत वनों की सुरक्षा और विकास में लोगों को शामिल करें । मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई सुचना के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग 8000 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां लगभग 4 मिलियन हेक्टयर वन क्षेत्र की सुरक्षा करने में कार्यरत हैं ।

Wireless sets for forest officials in M.P.

† * 383. SHRI BALKAVI BAIRAGI: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Central Government propose to provide wireless sets to all the forest officials of Madhya Pradesh, in order to keep a check on illegal felling of trees and for fire safety;

(b) if so, the number of wireless sets provided so far;

(c) the number of incidents of forest fire during 1998-99 and 1999-2000 in that State and the action taken by Government to check such incidents; and

(d) the action taken by Government to keep a check on illegal felling of trees in forests?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI T. R. BAALU): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Forest Protection is primarily the responsibility of the State Governments and State Governments provide funds under State Plan for forest protection activities. However, in order to strengthen the forest protection machinery, Central Government provides funds for procurement of wireless sets and other equipment under various Centrally sponsored Schemes.

† Original notice of the question was received in Hindi.

(b) Under the various Centrally sponsored schemes, 1215 Wireless sets have been sanctioned to the Government of Madhya Pradesh.

(c) The Madhya Pradesh Forest Department have reported that the following fire incidents have been reported.

Year	—	No. of fire incidents
1998-99	–	619
1999-2000		1012

The fire incidents were controlled through prompt action for suppression and use of equipment supplied under fire protection schemes and help from the local people.

(d) The Central Government had advised the States to strengthen the forest protection machinery and involve the people in forest protection and development under JFM Programme. As per the information furnished by the Madhya Pradesh Government around 8,000 Joint Forest Management Committees are protecting around 4 million ha. of forests in Madhya Pradesh.

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, माननीय वन मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर अधूरा दिया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न के "घ" भाग के उत्तर मे बताया है कि "मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में लगभग आठ हजार संयुक्त वन प्रबंधन समितियां लगभग चार मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र की सुरक्षा करने में कार्यरत हैं ।" मेरा ऐसा विश्वास है कि जो नियम और कानून मध्य प्रदेश पर लागू होते हैं, वह सारे देश पर लागू होते हैं । मैं माननीय वन मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो प्रदेश की सरकारें वन प्रबंधन की समितियां बनाती हैं और जैसे कि मध्य प्रदेश में 8000 समितियां काम कर रही हैं, इन समितियों के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से प्रोत्साहन के तौर पर क्या किसी प्रोत्साहन राशि या प्रबंधन के लिये किसी राशि का प्रावधान है ? अगर है तो कितना है और नहीं है तो क्या किसी ऐसी राशि का प्रावधान करने की सरकार की नीयत या इच्छा है, यह मेरा पहला प्रश्न आपसे है ।

SHRI T. R. BAALU: Mr. Chairman, Sir, there are 36135 JFM Committees in the country, and they are servicing an area of 1,02,48,586 hectares in 22 States. In order to strengthen the JFM

activities, JFM Cells have been created. We are also providing Rs. 30 lakhs in the year 2001-2002 for strengthening the JFM activities. For the purpose of strengthening the Working Group of JFM, we will be providing Rs. 20 lakhs in the year 2001-2002. For monitoring the impact assessment and data collection of JFM programmes, we will be providing Rs. 25 lakhs in that particular year. For the purpose of research and training in the field, we will be providing Rs. 15 lakhs. For providing aid to the JFM Committees for setting up of their offices, wc will be providing Rs. 10 lakhs with a maximum of Rs. 25,000 per committee. So, by 2001-2002, a total of Rs. 1 crore would have been provided to them.

श्री बालकवि बैरागीः माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि केन्द्रीय सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत वनों में जो आपदाएं पैदा हो जाती हैं जैसे आग लग जाती है या नुकसान हो जाता है तो इनके लिये वायरलैस सेट देती है । क्या इसके लिये केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों के माध्यम से कुछ व्यवस्था करने की कोशिश की है ? आपने मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा दिया है, इसमें 1215 वायरलैस सेटों की स्वीकृति दी गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने कुल कितने वायरलैस सेट आपसे मांगे थे या चाहे थे कि इतने वायरलैस सेट हमको चाहिये क्योंकि मध्य प्रदेश में वन सम्पदा बहुत है और मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद भी बहुत बड़ा वन का हिस्सा मध्य प्रदेश के पास है । तो इन 1215 वायरलैस सेटों के अलावा कितने सेट और मांगे गये थे और कितने सेट आप इस साल देने के लिये तैयार हैं, यह सरकार को आज्ञा दे देंगे उसका प्रावधान कर देंगे ?

SHRI T. R. BAALU: Sir, the forest fire has affected 6 per cent of our forest area. About 3.7 million hectares of our forest area is being affected by it every year; and, due to this fire, every year, we are losing Rs. 440 crores. Initially, in the Ninth Plan, wc had provided Rs. 15 crores for the protection of forests. Now it has been increased to Rs. 40 crores. As far as Madhya Pradesh is concerned, wc have extended financial assistance to them for purchasing 1215 wireless sets. Hundred per cent grant is available for purchasing these wireless sets. If there is any proposal, definitely, we will consider that. Sir, hundred per cent

grant will be extended to Madhya Pradesh for purchasing the wireless sets.

MR. CHAIRMAN: Shri Ahluwalia. Is your question relating to Madhya Pradesh?

SHRI S. S. AHLUWALIA: Yes, Sir. I am putting a question about Madhya Pradesh *on\y...(Interruptions)...* As I am a Member of the Council of States, I can put questions pertaining to the entire country.

MR. CHAIRMAN: No, no; this question is about Madhya Pradesh.

श्री एस. एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वन सम्पदा की रक्षा करने के लिये जो प्रावधान मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि मध्य प्रदेश के जंगलों की कोई भी लकड़ी, कोई भी काठ, कोई भी दरख्त या किसी भी वन सम्पदा को काटा नहीं जा सकता है पर उसकी सुरक्षा करते-करते वन सम्पदा की रक्षा करने के लिये आपके जो प्रहरी वहां पर हैं, चाहे उनके पास वायरलैस हैं, चाहे दोनाली बंदूक है, चाहे लाठी है पर उस वन सम्पदा के साथ-साथ वन में जो खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, उनकी जो खुले आम चोरी हो रही है, और बहुमूल्य खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं वन अधिकारियों के साथ मिलकर, उसकी कितनी कंप्लेंट्स आपके पास आई है और उन पर क्या कार्यवाही आपने की है ?

SHRI T. R. BAALU: The Central Government has not received any such complaints from the State so far. We will collect, compile and sent it to the hon. Member. Sir, it is a social menace, and the Central as well as the State Governments have to address the problem.

श्री विक्रम वर्मा : माननीय सभापति जी, अभी जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि मध्य प्रदेश की सरकार को 1215 वायरलैस सेट दिये गये हैं । आप यह देखें कि जो आग की घटनाएं हुई हैं, फायर इन्सिडेंट्स हुये हैं 1998-99 में 619 थे और 1999-2000 में 1012 हुये अर्थात् इनकी संख्या बढ़ी है । केन्द्र द्वारा वायरलैस सेट का शत-प्रतिशत अनुदान देने के बाद भी यह स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की सरकार को उस आग को रोकने के लिये जो प्रिकाशन्स लेना चाहिए, इन सुविधाओं के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले में असमर्थ रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र ने इसको रोकने के बारे में बातचीत की है ? दूसरी

बात यह है कि पहले यह पता लगाया जाए कि मध्य प्रदेश की सरकार 1215 वायरलैस सेटों का उपयोग कर रही है या नहीं कर रही है ? क्योंकि मुझे मालूम है वहां फारेस्ट गार्ड को देने के लिये दुनाली बंदूकें खरीदी गईं और वे दस साल तक पड़ी रहीं, उनको डिस्ट्रिब्यूट तक नहीं किया गया । फोरेस्ट गार्ड के ऊपर हमले होते रहे । जब वहां इस प्रकार की घटनाएं होती रही हैं तो पहले यह पता लगाया जाए कि 1215 वायरलैस सेट काम में लाए जा रहे हैं या नहीं लाए जा रहे हैं ? इसके बाद जो 1012 फायर की घटनाएं हुई हैं, इनको रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं, इस बारे में क्या बातचीत हुई है ?

SHRI T. R. BAALU: Sir, actually, Madhya Pradesh is one of the best managed States as far as forest development is concerned. We are interacting with them. Three months back, I visited Madhya Pradesh. We are having frequent interaction with the State Forest Minister and, so far, I have received no such request or complaint.

Save Higher Education Day

*384. SHRI V. V. RAGHAVAN:
SHRI J. CHITHARANJAN:†

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether members of the Federation of Central Universities Teachers Association observed a Save Higher Education Day and organised a hunger strike on November 22, to protest against withdrawal of the University Grants Commission's earlier notifications;

(b) if so, the details of the notifications withdrawn by UGC; and

(c) what is the reaction of Government on that protest and their demands?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, MINISTER OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF OCEAN DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

† The Question was actually asked on (he floor of the House by Shri J. Chitharanjan.